International Research Journal of Management Science & Technology

IRJMST

ISSN 2250 – 1959(0nline)
2348 – 9367 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMST.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का गोरखपुर की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव : एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ० शैलेश गुप्ता
विद्यालय अध्यापक, भूगोल, राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिधॉव, बगहा–2, पश्चिमी चम्पारण, बिहार

सारांश :

प्रस्तुत शोध गोरखपुर जनपद के विभिन्न विकासखण्डों में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें 475 लोगों से प्राथमिक आँकड़े एकत्र किए गए। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग किस प्रकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे प्रमुख सामाजिक आयामों को प्रभावित कर रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों की संख्या अधिक है, वहाँ लोगों की शैक्षिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। सर्वेक्षित व्यक्तियों में से अधिकांश ने यह स्वीकार किया कि उद्योगों से प्राप्त आय ने न केवल उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया है बल्कि बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च वहन करने की क्षमता भी बढ़ाई है। विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा और निजी विद्यालयों की ओर झुकाव उन परिवारों में अधिक देखा गया, जिनका संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों से है। इसी प्रकार स्वास्थ्य स्थिति के विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़े परिवारों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, अस्पतालों तक पहुँच और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जैसी प्रवृत्तियाँ अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं। औद्योगिक गतिविधियों से प्राप्त आय ने उन्हें निजी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने तथा पोषण–संपन्न आहार अपनाने में सक्षम बनाया है, जबकि उद्योगों से वंचित परिवार अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या परम्परागत उपचार पद्धतियों पर निर्भर हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों ही क्षेत्रों में लैंगिक अंतर धीरे–धीरे घट रहा है, किंतु ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले विकासखण्डों में महिलाओं की शिक्षा और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता अब भी सीमित है। समग्र रूप से शोध यह सिद्ध करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग न केवल रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी प्रत्यक्ष रूप से सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोरखपुर के विभिन्न विकासखण्डों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि जहाँ उद्योगों का प्रसार अधिक है, वहाँ सामाजिक प्रगति भी तीव्र गति से हो रही है, जबकि जिन क्षेत्रों में उद्योगों का अभाव है, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही स्तरों पर चुनौतियाँ विद्यमान हैं। अतः यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि गोरखपुर जनपद के सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित करने, महिला सहभागिता बढ़ाने तथा शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को औद्योगिक विकास के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग न केवल क्षेत्रीय आर्थिक परिवर्तन के वाहक हैं बल्कि सामाजिक स्थिति के उन्नयन में भी अहम कड़ी के रूप में सामने आते हैं।

सूचक शब्द : शिक्षा, स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, आत्मनिर्भरता, महिला सहभागिता।

परिचय :

भारत जैसे विकासशील देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र को न केवल आर्थिक प्रगति का आधार माना जाता है, बल्कि यह सामाजिक उन्नति और जीवन स्तर में सुधार का भी प्रमुख साधन है। बड़े उद्योगों की तुलना में यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश के साथ अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न करता है और ग्रामीण तथा अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में लोगों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। गोरखपुर जनपद, जो पूर्वांचल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लंबे समय से शैक्षिक, स्वास्थ्य और रोजगार की चुनौतियों से जूझता रहा है। यहाँ की जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि पर आधारित रही है, किन्तु कृषि की सीमित संभावनाओं और संसाधनों के दबाव के कारण लोगों का झुकाव धीरे–धीरे औद्योगिक गतिविधियों की ओर बढ़ा है। विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों ने यहाँ के लोगों को रोजगार और आय का साधन उपलब्ध कराया है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति

में परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार है और आर्थिक आय में वृद्धि के साथ–साथ लोगों की शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। गोरखपुर के कई विकासखण्डों में यह देखा गया है कि उद्योगों से जुड़ी आय ने परिवारों को बच्चों की पढ़ाई–लिखाई, विशेषकर निजी विद्यालयों और तकनीकी शिक्षा की ओर प्रवृत्त किया है। महिला शिक्षा में भी सकारात्मक परिवर्तन सामने आए हैं, जिससे लैंगिक असमानता में धीरे–धीरे कमी देखी जा रही है। इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। रोजगार और आय में वृद्धि से लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आसान हुई है और वे सरकारी अस्पतालों के साथ–साथ निजी स्वास्थ्य संस्थानों का लाभ उठाने में सक्षम हुए हैं। पोषण–संपन्न आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और मातृ–शिशु स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना, उद्योगों से जुड़ी आय का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके विपरीत, जिन विकासखण्डों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक गतिविधियाँ सीमित हैं, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में पिछड़ापन अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। गोरखपुर जैसे जनपद में जहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के क्षेत्र मौजूद हैं, वहाँ उद्योगों का प्रसार असमान है, जिसके कारण सामाजिक स्थिति में भी असमानता देखने को मिलती है। यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का प्रभाव समझना आवश्यक है, ताकि नीति–निर्माण की प्रक्रिया में औद्योगिक विकास और सामाजिक उन्नति के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

अध्ययन क्षेत्र :

गोरखपुर जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और आर्थिक केंद्र के रूप में स्थित है। यह जिला 26°13′ से 27°29′ उत्तर अक्षांश तथा 83°05′ से 83°56′ पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है, जो इसे राज्य के उत्तर–पूर्वी भाग में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। इसकी भौगोलिक सीमाएं महत्त्वपूर्ण जनपदों से मिलती हैं, उत्तर में महराजगंज, पूर्व में कुशीनगर एवं देवरिया, दक्षिण में आजमगढ़ एवं मऊ तथा पश्चिम में संत कबीर नगर एवं अंबेडकर नगर। यह अंतरजनपदीय स्थिति न केवल गोरखपुर को प्रशासनिक दृष्टि से रणनीतिक बनाती है, बल्कि इसके आर्थिक एवं औद्योगिक संपर्कों को भी सशक्त करती है। औद्योगिक दृष्टिकोण से गोरखपुर जनपद की भूमिका दिनों–दिन सशक्त होती जा रही है। यहाँ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की एक सशक्त श्रृंखला विकसित हो रही है, जो कृषि आधारित, वनोपज आधारित, हथकरघा, काष्ठ, फर्नीचर, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, निर्माण सामग्री, हस्तशिल्प एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योगों में सक्रिय हैं। यह जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की रीढ़ बनकर उभरा है, जहाँ पर औद्योगिक क्लस्टरों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, विद्युत आपूर्ति, परिवहन नेटवर्क और वाणिज्यिक बाजारों का सघन विकास हुआ है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र यहाँ के लघु एवं मध्यम उद्योगों को बेहतर अवसंरचना, भूमि, जल, बिजली, और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिससे रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

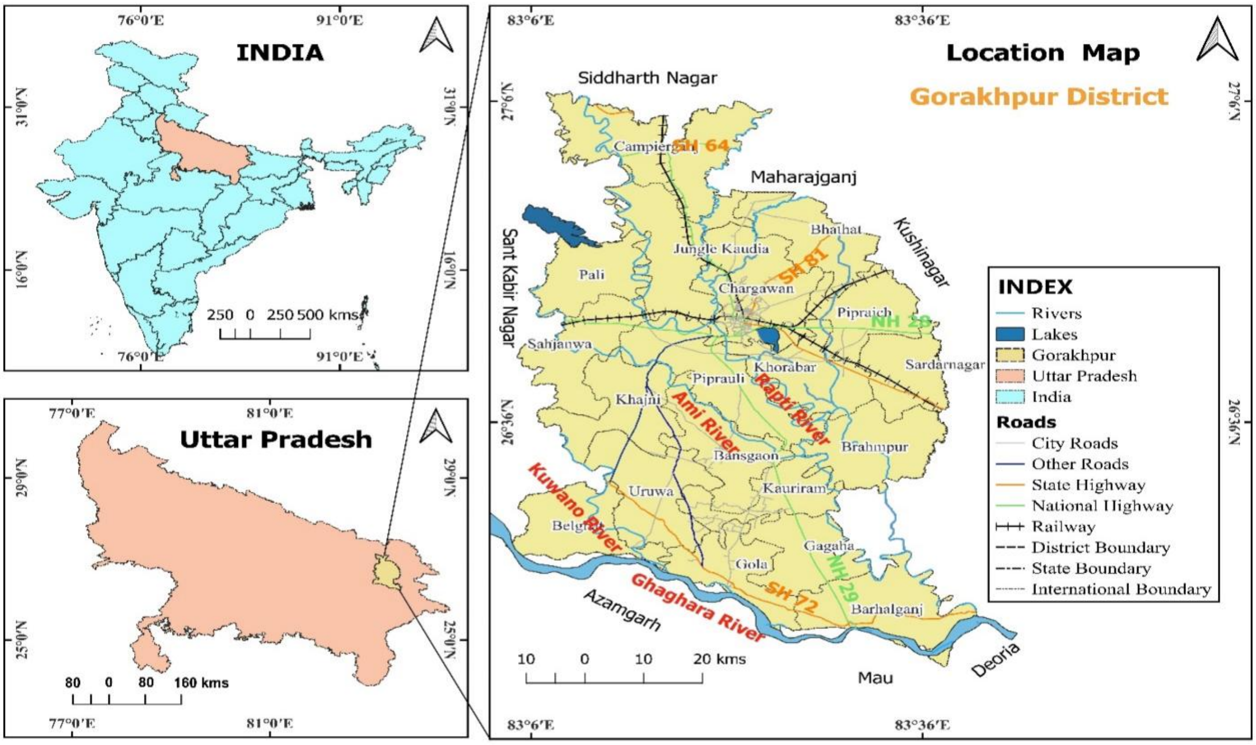

मानचित्र संख्या 01 : जनपद का अवस्थिति मानचित्र।

उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़े परिवारों की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़े परिवारों की स्वास्थ्य स्थिति का विश्लेषण करना।
- गोरखपुर जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से सामाजिक स्थिति सुधार हेतु चुनौतियों और संभावनाओं की पहचान करना।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रभाव के आधार पर नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

आंकड़ा स्रोत तथा शोध विधि तंत्र :

अध्ययन हेतु गोरखपुर जनपद के सभी 19 विकासखण्डों को शोध का आधार बनाया गया तथा अनुसंधान तकनीक के रूप में स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति को अपनाया गया है। इस पद्धति का चयन इसलिए किया गया ताकि प्रत्येक विकासखण्ड से समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके और क्षेत्रीय विषमता को भी ध्यान में रखा जा सके। सर्वप्रथम प्रत्येक विकासखण्ड को एक स्तर के रूप में मानकर उसमें से 5–5 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का यादृच्छिक चयन किया गया। इस प्रकार कुल 95 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अध्ययन में सम्मिलित किए गए। तत्पश्चात प्रत्येक चयनित उद्योग के आसपास के क्षेत्र से 5–5 व्यक्तियों का चयन कर प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया, जिससे उद्योगों के प्रत्यक्ष लाभार्थियों एवं स्थानीय समाज पर उनके प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। इस प्रकार 95 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से जुड़े 475 उत्तरदाताओं को सर्वेक्षण हेतु चुना गया। आकडां संग्रहण के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत संरचित प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं प्रत्यक्ष अवलोकन तकनीकों का प्रयोग किया गया, जबकि द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध प्रबंधों, सरकारी रिपोर्टों तथा विभिन्न विभागीय आंकड़ों का उपयोग किया गया। प्रश्नावली में उत्तरदाताओं की सामाजिक स्थिति, विशेषकर शिक्षा स्तर एवं स्वास्थ्य स्थिति (स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, रोग निवारण, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, पोषण आदि) से संबंधित प्रश्न सम्मिलित

किए गए। एकत्रित आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण सरल गणना, प्रतिशत, अनुपात तथा तुलनात्मक अध्ययन की विधियों द्वारा किया गया, जबकि परिणामों को तालिकाओं एवं आरेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण :

गोरखपुर की सामाजिक संरचना परंपरा और विविधता पर आधारित है, जिसमें जाति, धर्म, वर्ग, लिंग और शहरी–ग्रामीण विभाजन की प्रमुख भूमिका है। यहाँ हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय रहते हैं, जिनमें हिन्दू बहुसंख्यक हैं और उनके भीतर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित तथा पिछड़ी जातियाँ शामिल हैं। अनुसूचित जाति–जनजातियाँ भी यहाँ की जनसंख्या का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनकी स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है, परंतु अभी भी उन्हें समान अवसरों की प्राप्ति में कठिनाइयाँ हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक ढांचा भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत बंधन और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था अब भी प्रभावी हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और शहरीकरण के कारण सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है और जातिगत प्रतिबंध कमजोर हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गोरखपुर विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों ने युवाओं में सामाजिक जागरूकता और लैंगिक समानता की सोच विकसित की है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक प्रभाव आज भी गहरा है। धार्मिक दृष्टि से गोरखपुर बहुधार्मिक सह–अस्तित्व का प्रतीक है, जहाँ विभिन्न समुदायों के पर्व और धार्मिक स्थल एक साथ विद्यमान हैं, यद्यपि कभी–कभी साम्प्रदायिक तनाव भी सामने आते हैं। परिवार संस्था भी यहाँ महत्वपूर्ण है। संयुक्त परिवार अभी भी प्रचलित हैं, लेकिन एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। आर्थिक स्तर पर निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, जिनकी जीवनशैली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है।

गोरखपुर की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक कृषि और पारंपरिक व्यवसायों पर आधारित रही, जिससे जातिगत पेशों और सामाजिक पदानुक्रम की स्थिरता बनी रही। परंतु हाल के वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास ने इस ढांचे में बदलाव शुरू किया है। हस्तशिल्प, खिलौने, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत जैसे क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित हुए हैं, जिनसे विभिन्न वर्गों को रोजगार मिला और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी। इससे समाज में समानता और समरसता की भावना मजबूत हुई। महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों को उद्यमिता के अवसर मिलने से पारंपरिक सामाजिक बंधनों में ढील आई और उनमें आत्मविश्वास विकसित हुआ। इससे वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कारण ग्रामीण–शहरी पलायन में कमी आई है क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलने से नई सामाजिक चेतना का विकास हुआ है, जो युवाओं को नवाचार और उद्यमशीलता की ओर प्रेरित कर रही है। अतः गोरखपुर की सामाजिक संरचना अब परंपरा और आधुनिकता के समन्वय की ओर अग्रसर है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास को भी सशक्त बना रहे हैं।

1. स्वास्थ्य :

स्वास्थ्य सामाजिक विकास का अभिन्न अंग है, किंतु 1950–60 के दशकों में इसे उपेक्षित माना गया और आर्थिक विकास को ही मुख्य लक्ष्य माना गया। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि असमानताओं को कम करने और समग्र विकास हेतु स्वास्थ्य सुधार आवश्यक है। स्वास्थ्य मानव पूंजी की गुणवत्ता, श्रमशक्ति की कार्यक्षमता और सामाजिक कल्याण का निर्धारण करता है। अच्छे स्वास्थ्य से लोग अधिक समय तक काम करने, उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक–सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने में सक्षम होते हैं, जबकि खराब स्वास्थ्य से उत्पादकता घटती है और परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में आर्थिक विकास से संबंध है। प्रत्यक्ष प्रभाव तब दिखता है जब सरकार अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण और पोषण योजनाओं में निवेश करती है, जिससे रोजगार सृजन और स्वास्थ्य ढाँचे का विकास होता है। परोक्ष रूप से शिक्षा, स्वच्छता, पोषण और स्वस्थ जीवनशैली से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। विश्व बैंक और डब्ल्यूएचओ ने भी रेखांकित किया है कि स्वस्थ जनसंख्या श्रम लागत घटाती, अवकाश कम करती और उत्पादकता बढ़ाती है। विशेषकर विकासशील देशों में स्वास्थ्य आर्थिक वृद्धि की धुरी है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं

से शिशु मृत्यु दर घटती है, जीवन प्रत्याशा बढ़ती है और सामाजिक–आर्थिक स्थिरता आती है। भारत जैसे देश में, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, वहाँ निवेश की प्राथमिकता अनिवार्य है। गोरखपुर में हाल के वर्षों में मातृ–शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण में सुधार हुआ है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी स्वास्थ्य सेवाएँ सीमित हैं। यदि इन्हें सशक्त किया जाए, तो श्रमशक्ति अधिक उत्पादक बनेगी और कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ेगी। स्वस्थ समाज नवाचार, शिक्षा और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य केवल सामाजिक कल्याण ही नहीं, बल्कि आर्थिक समृद्धि और क्षेत्रीय विकास का आधार है।

तालिका संख्या 01 : गोरखपुर जनपद में स्वास्थ्य की स्थिति, 2019–2021।

क्र०सं०	संकेतक	जनपद गोरखपुर		
		NFHS-4	NFHS-5	परिवर्तन
1	बिजलीयुक्त घर	78.0	94.9	16.9
2	बेहतर पीने के पानी की सुविधा युक्त घर	99.8	99.8	00
3	बेहतर स्वच्छता सुविधा युक्त घर	37.7	69.6	31.9
4	खाना पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले घर	39.7	66.8	27.1
5	जिन घरों में कोई भी सदस्य स्वास्थ्य बीमा से लाभान्वित है	7.8	17.9	10.1
6	संस्थागत प्रसव	76.7	91.6	14.9
7	संस्थागत प्रसव जो सरकारी अस्पताल में हुए	52.5	72.5	20
8	जिन महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से कम है	22.2	18.0	–4.2
9	एनीमिया से पीड़ित महिलाएं (15–49 वर्ष की आयु वाली)	51.7	52.9	1.2
10	महिलाएं जिन्होने ने कम से कम 4 बार प्रसवपूर्व जांच कराई है	35.2	56.3	21.1
11	महिलाएं जिन्हे प्रसव के 2 दिनों के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त हुआ	64.7	79.1	14.4

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 और 5, 2019–2021।

गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (2015–16) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2019–21) के बीच स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण से जुड़े संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है। यह परिवर्तन सरकारी योजनाओं, जागरूकता अभियानों और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुँच का परिणाम है।

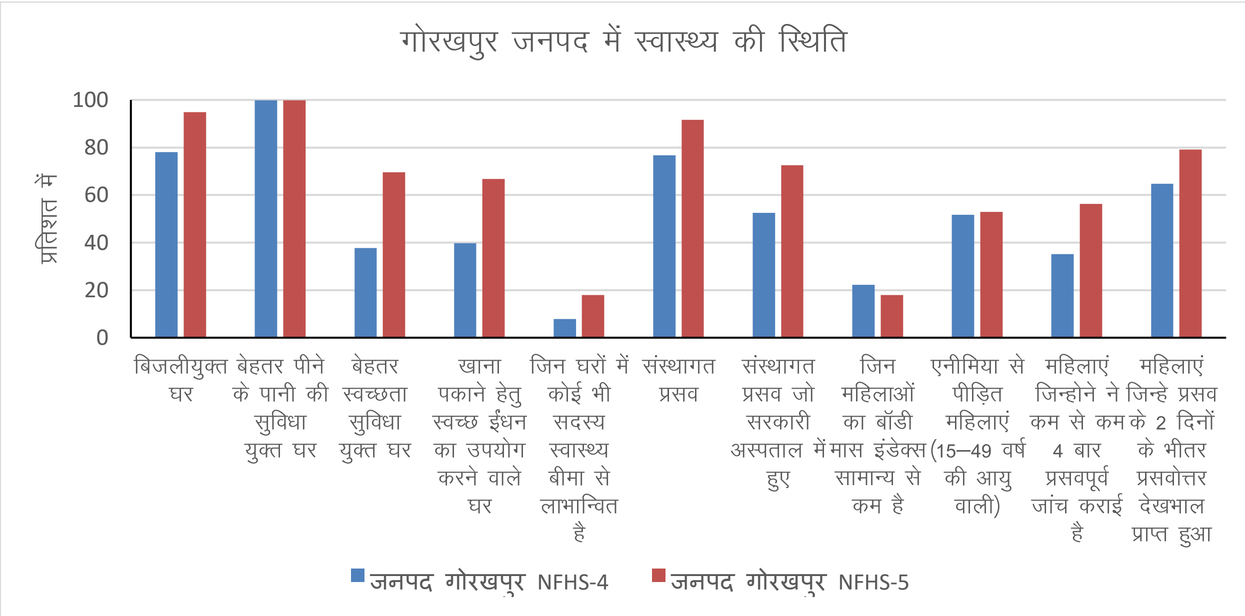

आरेख संख्या 01 : गोरखपुर जनपद में स्वास्थ्य की स्थिति।

बिजली से युक्त घरों का प्रतिशत 78.0 से बढ़कर 94.9 हो गया, जो सौभाग्य योजना जैसी पहल की सफलता दर्शाता है। पीने के पानी की सुविधा पहले से ही लगभग शत–प्रतिशत (99.8) थी, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। खुले में शौच से मुक्त घरों का प्रतिशत 37.7 से 69.6 हो गया, जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण और व्यवहार परिवर्तन का सकारात्मक परिणाम है। खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपयोग करने वाले घरों का प्रतिशत 39.7 से 66.8 हुआ, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जाता है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष लाभ हुआ। स्वास्थ्य बीमा से लाभान्वित घरों का प्रतिशत 7.8 से बढ़कर 17.9 हो गया, जो आयुष्मान भारत और राज्य स्तरीय योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। संस्थागत प्रसव 76.7 से बढ़कर 91.6 प्रतिशत हुए और इनमें सरकारी अस्पतालों का योगदान 52.5 से 72.5 प्रतिशत तक पहुँचा, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। सामान्य से कम बीएमआई वाली महिलाओं का प्रतिशत 22.2 से घटकर 18.0 हुआ, जो पोषण कार्यक्रमों की सफलता है। हालांकि 15–49 वर्ष की एनीमिक महिलाओं में वृद्धि (51.7 से 52.9) चिंताजनक है, जो आहार और आयरन सप्लीमेंटेशन में और सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। चार बार प्रसवपूर्व जांच कराने वाली महिलाओं में 21.1 अंकों की वृद्धि (35.2 से 56.3) और प्रसवोत्तर देखभाल में 14.4 अंकों की वृद्धि (64.7 से 79.1) दर्ज हुई, जो मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और आशा कार्यकर्ताओं की सक्रियता का परिणाम है।

तालिका संख्या 02 : जनपद में सर्वेकृत लोगों की विकासखण्डवार स्वास्थ्य की स्थिति, 2024।

विकासखण्ड	मातृत्व देखभाल	संस्थागत प्रसव	पेयजल सुविधा	शौचालय सुविधा	विद्युतयुक्त घर	स्वास्थ्य बीमा	कुल स्वास्थ्य सूचकांक
पाली	0.84	0.88	0.92	0.72	0.92	0.24	0.753
सहजनवा	0.92	0.80	0.96	0.76	0.96	0.32	0.786
पिपरौली	0.84	0.88	1.00	0.72	0.88	0.28	0.766
जंगल कौड़िया	0.80	0.92	0.96	0.68	0.84	0.16	0.726
चरगांवा	0.96	0.96	1.00	0.92	1.00	0.60	0.906
भटहट	0.64	0.88	0.96	0.80	1.00	0.48	0.793
पिपराइच	0.64	0.92	0.96	0.72	0.96	0.48	0.780
सरदारनगर	0.68	0.80	0.92	0.76	0.84	0.56	0.760
खोराबार	0.56	0.92	0.96	0.88	0.92	0.40	0.733
ब्रम्हपुर	0.88	0.84	0.92	0.84	0.88	0.36	0.786
कौड़ीराम	0.84	0.80	0.88	0.76	0.96	0.28	0.753
बॉसगांव	0.72	0.88	0.96	0.80	0.84	0.44	0.773
उरुवा	0.60	0.84	0.96	0.84	0.80	0.52	0.760
गगहा	0.64	0.80	0.88	0.64	0.92	0.32	0.700
खजनी	0.84	0.76	0.92	0.84	0.96	0.24	0.760
बेलघाट	0.68	0.80	0.96	0.80	1.00	0.36	0.766
गोला	0.72	0.72	0.92	0.72	0.92	0.24	0.706
बड़हलगंज	0.44	0.80	0.88	0.76	0.96	0.28	0.686
कैम्पियरगंज	0.48	0.84	0.92	0.68	0.92	0.24	0.680
योग जनपद	0.72	0.84	0.94	0.77	0.92	0.36	0.756

स्रोत :–शोधार्थी द्वारा संगणित, 2024।

प्रस्तुत तालिका 02 गोरखपुर जनपद के विभिन्न विकासखण्डों में सर्वेकृत लोगों की विकासखण्डवार स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाया गया है जो मातृत्व देखभाल, संस्थागत प्रसव, पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण और स्वास्थ्य

बीमा जैसे स्वास्थ्य विकास सूचकांकों का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें लगभग सभी सूचकांकों में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई है, विशेषकर संस्थागत प्रसव, शौचालय और विद्युतीकरण के क्षेत्र में। सबसे उल्लेखनीय सुधार पेयजल सुविधा में हुआ है, जहाँ अधिकांश विकासखण्डों ने 92 से 100 प्रतिशत तक की उपलब्धता हासिल की है। पिपराइच, पिपरौली और जंगल कौड़िया जैसे क्षेत्रों में यह स्तर 100 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, जो जल जीवन मिशन और हर घर जल जैसी योजनाओं की सफलता दर्शाता है। शौचालय सुविधा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण और खुले में शौच से मुक्ति अभियानों ने निर्णायक बदलाव लाया है। चौरीचौरा (92 प्रतिशत), खजनी (84 प्रतिशत) और बड़हलगंज (76 प्रतिशत) इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

संस्थागत प्रसव भी 0.88 प्रतिशत से बढ़कर लगभग सभी विकासखण्डों में 90 से 100 प्रतिशत तक पहुँच गया है। पिपराइच, सहजनवां, पिपरौली और गोला जैसे क्षेत्रों में यह स्तर सर्वाधिक है। यह परिवर्तन जननी सुरक्षा योजना, आशा कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संभव हुआ है। मातृत्व देखभाल में चरगांवा (96 प्रतिशत), सहजनवां (92 प्रतिशत) और गोला (76 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों ने सराहनीय प्रगति की है। इसका श्रेय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, टीकाकरण और पोषण अभियानों को जाता है। स्वास्थ्य बीमा में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है। चरगांवा (60 प्रतिशत), सरदारनगर (56 प्रतिशत) और उरूवा (52 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में गरीब वर्ग को आयुष्मान भारत और राज्य स्तरीय योजनाओं से लाभ मिला है। विद्युतीकरण लगभग सभी विकासखण्डों में 84 से 100 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। बांसगांव, खजनी, गोला, पिपरौली और पिपराइच जैसे क्षेत्रों में यह पूरी तरह से सफल रहा है, जिससे ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और लघु उद्योगों में सकारात्मक बदलाव आया है।

तालिका संख्या 03 : जनपद में सर्वेक्षण किये गये लोगों की विकासखण्डवार स्वास्थ्य की स्थिति, 2024।

श्रेणी	माध्य मान	विकासखण्डों की संख्या	विकासखण्ड
उच्च	0.800 से अधिक	1	चरगांवा
मध्यम	0.750–0.800	12	पाली, सहजनवा, पिपरौली, भटहट, पिपराइच, सरदारनगर, ब्रम्हपुर, कौड़ीराम, बॉसगांव, उरुवा, खजनी, बेलघाट
निम्न	0.750 से कम	6	जंगल कौड़िया, खोराबार, गगहा, गोला, बड़हलगंज, कैम्पियरगंज

स्रोत : शोधार्थी द्वारा संगणित, 2024।

उपरोक्त तालिका में गोरखपुर जनपद के विकासखण्डों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों – उच्च, मध्यम और निम्न में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण माध्य मान पर आधारित है, जो मातृत्व देखभाल, संस्थागत प्रसव, पेयजल सुविधा, शौचालय सुविधा, विद्युतयुक्त घरों और स्वास्थ्य बीमा जैसे सूचकों के सम्मिलित विश्लेषण से प्राप्त हुआ है। यह विभाजन जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की क्षेत्रीय असमानताओं को समझने का आधार प्रदान करता है।

- **उच्च श्रेणी (माध्य मान 0.800 से अधिक) :** इस श्रेणी में केवल चरगांवा विकासखण्ड आता है, जो जनपद का सबसे बेहतर क्षेत्र है। यहाँ प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता, चिकित्सकों की संख्या, संस्थागत प्रसव, मातृ एवं शिशु टीकाकरण तथा पोषण सेवाएँ संतोषजनक हैं। इसकी बेहतर स्थिति के पीछे नगरीय केंद्रों की निकटता, स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास, उच्च स्तर की जनजागरूकता और सरकारी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन प्रमुख कारक हैं।

- **मध्यम श्रेणी (माध्य मान 0.750 से 0.800) :** इस श्रेणी में 12 विकासखण्ड – पाली, सहजनवा, पिपरौली, भटहट, पिपराइच, सरदारनगर, ब्रम्हपुर, कौड़ीराम, बासगांव, उरुवा, खजनी और बेलघाट शामिल हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ औसत से बेहतर हैं, किंतु कई पहलुओं में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं, पर विशेषज्ञ चिकित्सकों, आपातकालीन सेवाओं, उच्च स्तरीय मातृ देखभाल और नवजात देखभाल की कमी पाई जाती है। संस्थागत प्रसव दर बढ़ी है, पर कुछ स्थानों पर पारंपरिक प्रसव प्रथाएँ प्रचलित हैं। टीकाकरण कवरेज और पोषण योजनाओं के कार्यान्वयन में भी असमानता देखी जाती है। यदि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना और जनजागरूकता को बढ़ावा दिया

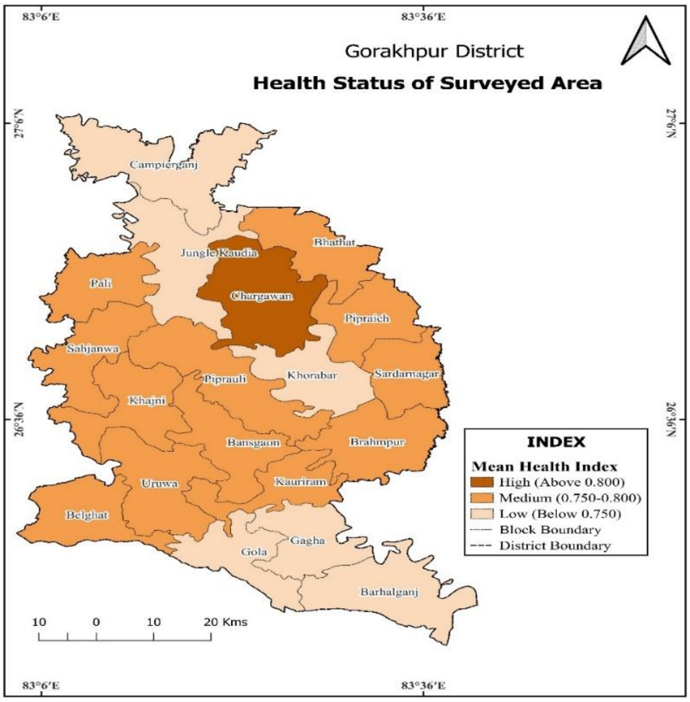

जाए, तो ये उच्च श्रेणी की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

मानचित्र संख्या 02 : जनपद में सर्वेकृत लोगों की विकासखण्डवार स्वास्थ्य की स्थिति, 2024।

- **निम्न श्रेणी (माध्य मान 0.750 से कम) :** इस श्रेणी में 6 विकासखण्ड – जंगल कौड़िया, खोराबार, गगहा, गोला, बड़हलगंज और कैम्पियरगंज आते हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता दोनों ही कमजोर हैं। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या सीमित है और प्रशिक्षित मानव संसाधन की भारी कमी है। प्रसवपूर्व देखभाल, कुपोषण, उच्च शिशु मृत्यु दर और नियमित टीकाकरण की कमी गंभीर समस्याएँ हैं। गरीबी, शिक्षा की कमी, परिवहन अवसंरचना का अभाव और सरकारी योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन से स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

निष्कर्षतः, यह स्पष्ट है कि गोरखपुर जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत विषम है। जहाँ चरगांवा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, वहीं गगहा और गोला जैसे विकासखण्ड अब भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्षरत हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए क्षेत्र–विशेष पर केंद्रित योजनाएँ, सुदृढ़ स्वास्थ्य अवसंरचना, व्यापक जनजागरूकता और स्थानीय स्वास्थ्यकर्मियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जब तक समावेशी और संतुलित स्वास्थ्य नीति लागू नहीं होती, तब तक सतत विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

2 शिक्षा :

गोरखपुर जनपद में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में जो वृद्धि दर्ज की गई, वह क्षेत्रीय विकास, सामाजिक चेतना और शैक्षिक योजनाओं की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। साक्षरता केवल पढ़ने–लिखने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक प्रगति और राजनीतिक भागीदारी का आधार

भी है। जनगणना के आँकड़े बताते हैं कि इस दशक में जनपद के सभी विकासखण्डों में साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विशेष रूप से महिला साक्षरता दर में हुई वृद्धि इस बात का संकेत है कि समाज में शिक्षा के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ी है और धीरे–धीरे लैंगिक असमानता की खाई कम हो रही है। उदाहरणस्वरूप, चरगांवा विकासखण्ड में 2001 में जहाँ कुल साक्षरता दर मात्र 44.72 प्रतिशत थी, वह 2011 में बढ़कर 61.03 प्रतिशत हो गई। इस दौरान महिला साक्षरता दर में लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो यह दर्शाती है कि ग्रामीण परिवेश में भी शिक्षा की पहुँच और स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। इसी प्रकार, पाली, सहजनवा, गोला और खोराबार जैसे विकासखण्डों में साक्षरता दर क्रमशः 69.11, 70.52, 71.88 और 66.74 प्रतिशत तक पहुँच गई, जबकि 2001 में ये आँकड़े लगभग 50 प्रतिशत के आसपास थे। यह वृद्धि शिक्षा अवसंरचना के विस्तार, विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, मिड–डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा विभिन्न छात्रवृत्तियों के प्रभाव का परिणाम है। साक्षरता की इस प्रगति ने गोरखपुर की सामाजिक संरचना में भी सकारात्मक बदलाव लाए हैं। महिलाओं की शिक्षा ने उन्हें घरेलू सीमाओं से बाहर निकालकर निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया है, जिससे परिवार और समाज दोनों की स्थिति सुदृढ़ हुई है। उच्च साक्षरता दर वाले विकासखण्डों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार नियोजन और बालिका शिक्षा जैसे क्षेत्रों में जागरूकता अधिक पाई जाती है। वहीं, जिन क्षेत्रों में साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है, वहाँ गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ापन अब भी विकास में बाधक बने हुए हैं।

तालिका संख्या 04 : जनपद में सर्वेक्षण किये गये लोगों की विकासखण्डवार शैक्षणिक स्थिति, 2024।

विकासखण्ड	अशिक्षित	शिक्षित						
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	हाई स्कूल	इंटरमीडिएट	स्नातक	परास्नातक / अन्य	कुल
पाली	0.32	0.16	0.08	0.20	0.08	0.12	0.04	0.68
सहजनवा	0.16	0.04	0.12	0.16	0.20	0.24	0.08	0.84
पिपरौली	0.28	0.08	0.04	0.12	0.12	0.16	0.20	0.72
जंगल कौड़िया	0.32	0.04	0.12	0.24	0.08	0.08	0.12	0.68
चरगांवा	0.16	0.08	0.04	0.12	0.12	0.24	0.24	0.84
भटहट	0.36	0.16	0.24	0.16	0.04	0.04	0.00	0.64
पिपराइच	0.28	0.08	0.04	0.24	0.28	0.00	0.08	0.72
सरदारनगर	0.28	0.36	0.24	0.04	0.08	0.00	0.00	0.72
खोराबार	0.32	0.08	0.28	0.04	0.08	0.12	0.08	0.68
ब्रम्हपुर	0.28	0.08	0.08	0.16	0.16	0.08	0.16	0.72
कौड़ीराम	0.24	0.32	0.04	0.12	0.12	0.04	0.12	0.76
बॉसगांव	0.24	0.16	0.12	0.08	0.04	0.32	0.04	0.76
उरुवा	0.28	0.12	0.16	0.04	0.16	0.24	0.00	0.72
गगहा	0.24	0.16	0.04	0.16	0.24	0.16	0.00	0.76
खजनी	0.28	0.28	0.20	0.16	0.08	0.00	0.00	0.72
बेलघाट	0.32	0.08	0.12	0.24	0.16	0.04	0.04	0.68
गोला	0.28	0.20	0.08	0.16	0.04	0.24	0.00	0.72
बड़हलगंज	0.24	0.08	0.32	0.24	0.04	0.08	0.00	0.76
कैम्पियरगंज	0.20	0.24	0.04	0.20	0.16	0.04	0.12	0.80
योग जनपद	0.27	0.14	0.12	0.16	0.12	0.12	0.07	0.73

स्रोत : शोधार्थी द्वारा संगणित, 2024।

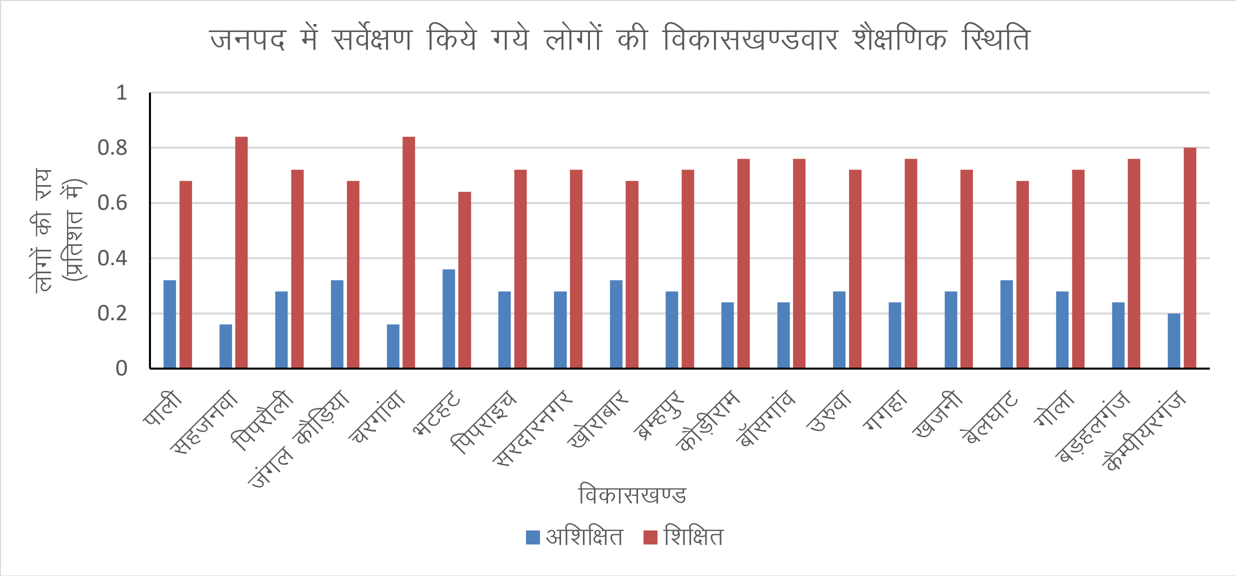

आरेख संख्या 02 : जनपद में सर्वेक्षण किये गये लोगों की विकासखण्डवार शैक्षणिक स्थिति, 2024।

प्रस्तुत तालिका गोरखपुर जनपद के विभिन्न विकासखण्डों में अशिक्षित एवं शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाती है, जो क्षेत्रीय सामाजिक–शैक्षणिक विकास की स्थिति को स्पष्ट करती है। यह अध्ययन 475 उत्तरदाताओं के शैक्षिक विचारों पर आधारित है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांश विकासखण्डों में शिक्षित जनसंख्या का अनुपात 68 से 84 प्रतिशत के बीच है। सहजनवा, पिपराइच, चरगांवा, गोला, बांसगांव और कौड़ीराम जैसे क्षेत्रों में यह अनुपात 70 प्रतिशत से अधिक है, जबकि पिपरौली, सरदारनगर, जंगल कौड़िया जैसे विकासखण्डों में यह आँकड़ा 68–72 प्रतिशत के बीच है। पिपराइच, पिपरौली और खजनी में यह अनुपात 84 प्रतिशत तक पहुँच जाना उल्लेखनीय है। इस शैक्षणिक प्रगति का श्रेय मुख्यतः सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मिड–डे मील योजना, कन्या शिक्षा प्रोत्साहन तथा डिजिटल शिक्षा जैसी योजनाओं को जाता है। विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रवृत्तियों की उपलब्धता और अभिभावकों की बदलती सोच ने ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाया है।

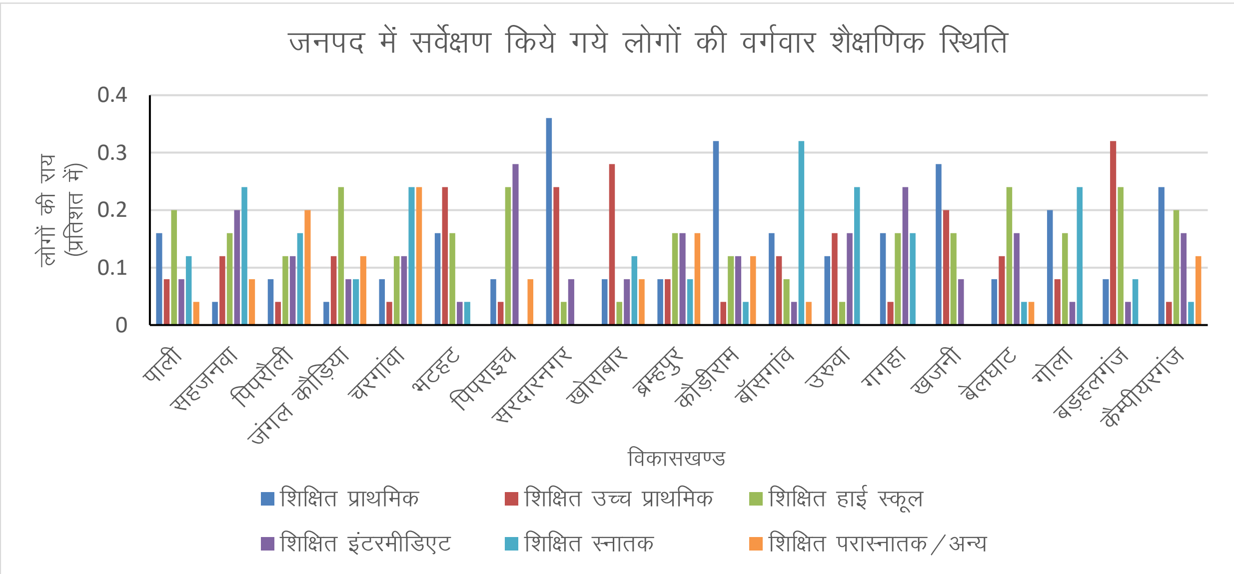

आरेख संख्या 03 : जनपद में सर्वेक्षण किये गये लोगों की वर्गवार शैक्षणिक स्थिति, 2024।

शिक्षा ने गोरखपुर की सामाजिक संरचना और आर्थिक गतिविधियों दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। शिक्षित जनसंख्या आधुनिक तकनीकों, प्रबंधन दक्षताओं और विपणन कौशल को अपनाने में सक्षम हो रही है। इससे कृषि–आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, जूट, वस्त्र एवं लकड़ी उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन

प्राप्त हो रहा है। विशेष रूप से युवा वर्ग अब पारंपरिक रोजगार से हटकर स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर अग्रसर हो रहा है, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हुई है। तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि शिक्षा का स्तर सभी विकासखण्डों में समान नहीं है। चरगांवा और खजनी जैसे क्षेत्रों में उत्तरदाता प्राथमिक स्तर तक अधिक केंद्रित हैं, जबकि बांसगांव, पिपराइच और कौड़ीराम में इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर के उत्तरदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। पिपरौली और जंगल कौड़िया जैसे क्षेत्रों में परास्नातक स्तर तक पढ़े लोग भी पाए गए, जो बेहतर शिक्षा सुविधाओं या बाहर जाकर पढ़ाई करने की प्रवृत्ति का संकेत है।

तलिका संख्या 05 : जनपद में सर्वेक्षण किये गये लोगों की विकासखण्डवार शैक्षणिक स्थिति, 2024।

श्रेणी	मान	विकासखण्डों की संख्या	विकासखण्ड
उच्च	0.80 से अधिक	3	सहजनवा, चरगांवा, कैम्पियरगंज
मध्यम	0.73–0.80	4	कौड़ीराम, बॉसगांव, गगहा, बड़हलगंज
निम्न	0.73 से कम	12	पाली, पिपरौली, जंगल कौड़िया, भटहट, पिपराइच, सरदारनगर, खोराबार, ब्रम्हपुर, उरुवा, खजनी, बेलघाट, गोला

स्रोत : शोधार्थी द्वारा संगणित, 2024।

प्रस्तुत तालिका गोरखपुर जनपद के विकासखण्डों को शैक्षिक स्थिति के आधार पर तीन वर्गों – उच्च, मध्यम और निम्न में विभाजित करती है। यह वर्गीकरण न केवल शिक्षा की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास की दिशा में क्षेत्रीय असमानताओं को भी उजागर करता है। साथ ही, यह नीति निर्माण और संसाधन आवंटन के लिए उपयोगी आधार प्रदान करता है।

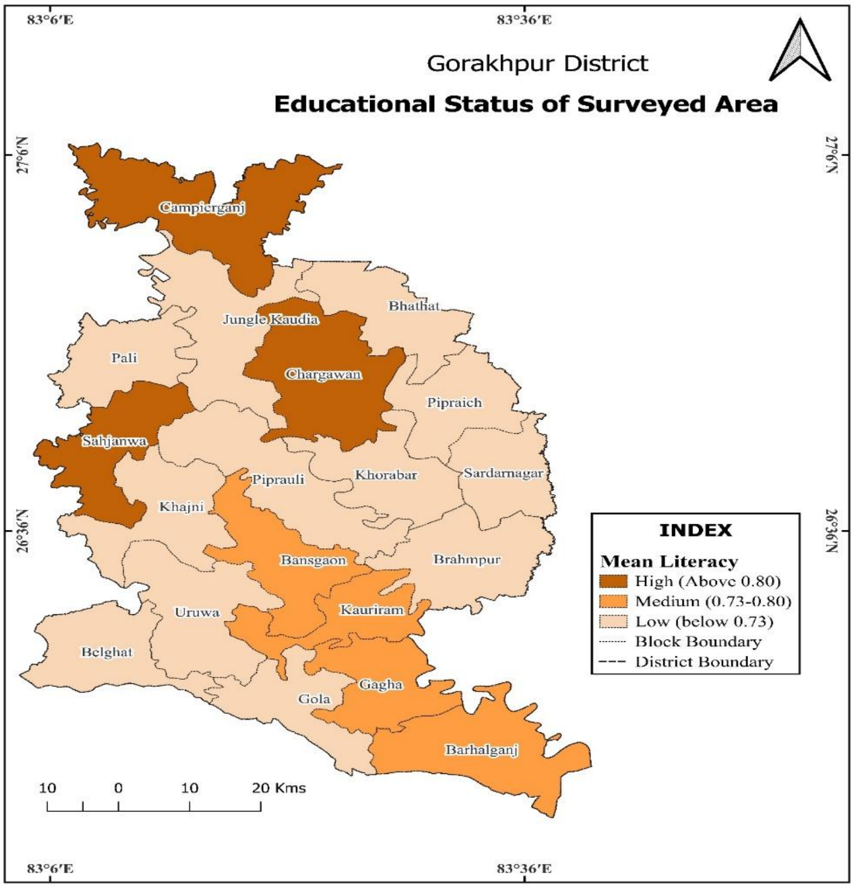

मानचित्र संख्या 03 : जनपद में सर्वेकृत लोगों की विकासखण्डवार शैक्षणिक स्थिति।

- **उच्च श्रेणी (0.80 से अधिक) :** इस श्रेणी में सहजनवा, चरगांवा और कैम्पियरगंज जैसे विकासखण्ड शामिल हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर है, जिसके पीछे कई कारक उत्तरदायी हैं। विद्यालयों की सुलभता, शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता, छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ और विशेष रूप से बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी ने शिक्षा को मजबूत आधार प्रदान किया है। पंचायत स्तर पर शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और महिला सशक्तिकरण ने भी इन क्षेत्रों की शैक्षिक प्रगति को गति दी है। साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास ने रोजगार और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया है, जिससे शिक्षा और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलित समन्वय स्थापित हुआ है।
- **मध्यम श्रेणी (0.73 – 0.80) :** इस वर्ग में कौड़ीराम, बांसगांव, गगहा और बड़हलगंज जैसे चार विकासखण्ड आते हैं। यहां शिक्षा की स्थिति संतोषजनक तो है, परंतु अब भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विद्यालयों की संख्या और गुणवत्ता में सुधार हुआ है, किंतु शिक्षक–छात्र अनुपात, तकनीकी शिक्षा की कमी और आधारभूत संरचना का अभाव इन क्षेत्रों की प्रगति को सीमित कर रहा है। फिर भी, ग्रामीण स्तर पर उद्यमशीलता की भावना विकसित हो रही है। लोग स्वरोजगार और स्थानीय संसाधनों के उपयोग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे भविष्य में यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से संभावनाशील बन सकता है।
- **निम्न श्रेणी (0.73 से कम) :** इस श्रेणी में 12 विकासखण्ड – पाली, पिपरौली, जंगल कौड़िया, भटहट, पिपराइच, सरदारनगर, खोराबार, ब्रम्हपुर, उरुवा, खजनी, बेलघाट और गोला आते हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अभी भी काफी कमजोर है। विद्यालयों की अपर्याप्त संख्या, शिक्षकों की कमी, शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव तथा बालिका शिक्षा में पिछड़ापन यहाँ की प्रमुख समस्याएँ हैं। साथ ही, गरीबी, सामाजिक रूढ़िवादिता और प्रशासनिक उदासीनता ने भी इन क्षेत्रों की प्रगति को प्रभावित किया है। शिक्षा की इस कमी ने न केवल सामाजिक विकास को बाधित किया है, बल्कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विस्तार को भी सीमित किया है, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी और पलायन की समस्या बनी हुई है।

समग्र रूप से यह स्पष्ट है कि गोरखपुर जनपद के विभिन्न विकासखण्डों में शैक्षिक और सामाजिक प्रगति असमान है। जिन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊँचा है, वहाँ उद्यमिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की संभावनाएँ भी अधिक हैं। वहीं, पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और उद्यम दोनों को समानांतर रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यह वर्गीकरण नीतिगत योजनाओं और संसाधन आवंटन में प्राथमिकता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा का स्तर न केवल सामाजिक उत्थान का प्रतीक है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था, उद्यमिता और युवाओं की आत्मनिर्भरता का भी आधार है। गोरखपुर जनपद में शिक्षा और उद्यमिता का यह समन्वय सतत् एवं समावेशी विकास की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध के व्यापक विश्लेषण के उपरांत यह स्पष्ट रूप से निष्कर्षित होता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र ने गोरखपुर जनपद की सामाजिक संरचना, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा शैक्षणिक परिदृश्य पर अत्यधिक गहरा और बहुआयामी सकारात्मक प्रभाव डाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (2015–16) से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2019–21) के मध्य दर्ज किए गए उल्लेखनीय सुधार – जैसे विद्युतयुक्त घरों का प्रतिशत 78.0 से बढ़कर 94.9, खुले में शौच से मुक्त घरों का प्रतिशत 37.7 से 69.6, स्वच्छ ईंधन उपयोग 39.7 से 66.8 प्रतिशत तक की वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा कवरेज में 7.8 से 17.9 प्रतिशत की प्रगति तथा संस्थागत प्रसव दर में 76.7 से 91.6 प्रतिशत तक का सुधार – ये सभी प्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा सृजित आर्थिक समृद्धि, रोजगार के अवसरों और बेहतर आय स्तर का परिणाम हैं। विकासखण्डों के स्वास्थ्य आधारित वर्गीकरण में चरगांवा का उच्च श्रेणी में स्थान, यह दर्शाता है कि जहाँ औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, वहाँ स्वास्थ्य सूचकांक भी बेहतर हैं। इसी प्रकार शैक्षणिक प्रगति में भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, जहाँ 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता दर में

व्यापक वृद्धि देखी गई और विशेष रूप से महिला साक्षरता में 21 प्रतिशत तक की प्रगति दर्ज की गई। 475 उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अधिकांश विकासखण्डों में शिक्षित जनसंख्या का अनुपात 68 से 84 प्रतिशत के मध्य है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक स्थिरता और रोजगार सुरक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम है। शैक्षणिक आंकडे स्पष्ट रूप से दर्शाते है कि औद्योगिक विकास और शैक्षणिक प्रगति के मध्य प्रत्यक्ष संबंध विद्यमान है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों ने न केवल प्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय व्यापार, सेवा क्षेत्र, परिवहन और कृषि आधारित गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया है, जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है और लोगों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का योगदान अत्यंत सराहनीय है, जहाँ खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तकनीकी कौशल विकास, उद्यमशीलता की संस्कृति का प्रसार और युवाओं के शहरी पलायन में कमी जैसे सकारात्मक परिवर्तन भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक विकास के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों ने गोरखपुर की सामाजिक स्थिति को न केवल सुदृढ़ किया है, बल्कि एक संतुलित, समावेशी और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, तथापि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतिगत सुधार और योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :

- Kumar, A. (2019). Micro, small and medium enterprises and socio-economic development in India. Journal of Rural Development, Vol.38(2), pp.245–262.
- Singh, R., & Verma, S. (2020). Role of MSMEs in rural transformation: A case study of Uttar Pradesh. Economic Affairs, Vol.65(4), pp.755–762.
- World Bank. (2018). Strengthening MSMEs for inclusive growth in India. Washington, DC: World Bank Publications.
- Pandey, P. (2017). MSMEs and their contribution to rural education and health in Eastern Uttar Pradesh. Indian Journal of Social Science Research, 12(3), pp.101–118.
- Gupta, V. (2016). Employment generation and poverty alleviation through MSMEs in India. Asian Economic Review, Vol.58(1), pp.89–104.
- United Nations Development Programme. (2021). Human development report 2020: The next frontier—Human development and the Anthropocene. UNDP.
- Srivastava, M., & Yadav, K. (2019). MSMEs and women empowerment in rural Uttar Pradesh. International Journal of Management Studies, Vol.7(3), pp.55–68.
- Government of India. (2018). District census handbook: Gorakhpur. Census of India 2011.
- Sharma, P. (2021). Health and education challenges in MSME clusters of North India. Journal of Development Policy and Practice, Vol.6(1), pp.66–84.
- Indian Council of Social Science Research. (2020). Research studies on small industries and regional development. ICSSR, New Delhi.
- Mishra, A. (2015). Impact of small-scale industries on rural social structure. Social Change Review, Vol.45(2), pp.230–248.
- Reserve Bank of India. (2020). Handbook of statistics on Indian economy. Mumbai: RBI.
- OECD. (2019). Enhancing SME productivity and inclusive growth in global value chains. Paris: OECD Publishing.

- Yadav, R., & Singh, H. (2022). Micro industries and health status in rural Uttar Pradesh: An empirical study. Journal of Health and Social Development, Vol.14(2), pp.77–95.
- Directorate of Industries, Uttar Pradesh. (2021). MSME sector in Uttar Pradesh: Opportunities and challenges. Lucknow: Government of Uttar Pradesh.
- Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises. (2023). Annual report 2022-23. Government of India.
- Planning Commission of India. (2011). Report of the working group on MSMEs growth for 12th five-year plan. Government of India.
- Government of Uttar Pradesh. (2022). Uttar Pradesh economic survey 2021-22. Lucknow: Department of Economics & Statistics.
- National Sample Survey Office (NSSO). (2021). Survey on unincorporated non-agricultural enterprises (excluding construction). Ministry of Statistics and Programme Implementation.
- International Labour Organization. (2020). The role of MSMEs in employment generation in South Asia. ILO Publications.

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

R E S E A R C H G A T E W A Y

A R O G Y A M O N L I N E

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM